



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 866]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2016/चैत्र 19, 1938

No. 866]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2016/ CHAITRA 19, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2016

का.आ. 1362(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनसे उसके प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य, छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा जिले में अवस्थित है और यह 351.240 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है;

भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य, एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है जो विविध वनस्पति और जीवजन्तु के समृद्ध वास स्थान के लिए जाना जाता है जिसमें बाघ, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, बनेला सूअर, लंगूर, मोर, भालू, लोमड़ी, नेवला, सांभर, जंगली कुत्ता, ब्लू बुल, जंगली भैंसा, बन्दर, खरगोश, लकड़बग्घा, अजगर, जंगली बिल्ली आदि सम्मिलित हैं।

और, भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य कान्हा टाइगर रिजर्व के लिए एक विस्तार प्रदान करता है साथ ही साथ भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य और अचानकमर टाइगर रिजर्व वन के बीच जंगली पशु के प्रवास / प्रवृत्ति के लिए एक गलियारे के रूप में कार्य करता है और भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य और कान्हा टाइगर रिजर्व को जोड़ता भी है और कान्हा और अचानकमर टाइगर रिजर्व के बीच है।

और, भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य, के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य जिला कवर्धा, की सीमा से 1 किलोमीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 0 से 1 किलोमीटर तक होगा और यह 109.882 वर्ग किलोमीटर (जिसके अंतर्गत 87.53 वर्ग किलोमीटर आरक्षित या संरक्षित वन और 22.35 वर्ग किलोमीटर राजस्व क्षेत्र भी है) के क्षेत्र में फैला हुआ है और जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत 15 गांव, अर्थात् राजाघर, रानीघर, रारोंदांदादार, पलक, चौरा, सरकिनाचहार, भंडलाटोला, बंछा, झारपट, भुरवाही, बरिया, झालामाना, बदलपानी, लहवार और समानापुरटोला आते हैं।

(3) प्रमुख बिंदुओं के अक्षांश तथा रेखांश के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) शहरी विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;

- (viii) छत्तीसगढ़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, पैरा 4 के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 10, 21, 26, 27 और 28 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ बनाना ;
- (iii) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं;
- (iv) वर्षा जल संचयन; और
- (v) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ।

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई वृटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में संशोधित होगी और उक्त वृटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप-पैरा के अधीन यथा-उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत** -आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन** - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शक द्वारा जारी (समय-समय पर यथा-संशोधित) सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और प्रवृत्त नियमों और इसके अध्यक्षीन बनाए गए विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इकाइयां**

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों का स्थापना विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग के सिवाय अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण के कोई नए उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के

		<p>संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का संनिर्माण के संदर्भ में प्रतिषिद्ध होंगी अन्यथा नहीं ;</p> <p>(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।</p>
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(4)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	सिवाय आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात के किसी संनिर्माण कार्यकलाप को 1 से 10 से अधिक ढाल वाली पहाड़ियों पर और किसी नदी और प्राकृतिक नाले से लगभग 100 मीटर तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
(7)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	प्लास्टिक थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
विनियमित क्रियाकलाप		
(10)	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं।
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:</p> <p>परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी ।</p> <p>(ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण कार्यकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और</p>

		<p>विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे।</p> <p>(ग) 1 किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए सन्निर्माण और अन्य सन्निर्माण कार्यकलापों को महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।</p> <p>(घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे</p>
(12)	ट्रेन्चिंग ग्राउंड।	किसी नए ट्रेन्चिंग ग्राउंड की स्थापना प्रतिषिद्ध है। पुराने ट्रेन्चिंग ग्राउंड को लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(13)	प्राकृतिक जल में बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(14)	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(15)	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(16)	भूमिगत जल की निकासी।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(17)	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किसी वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।</p> <p>(ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्यकरण योजना निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा।</p>
(18)	प्रवासी चारवाहे।	लागू विधियों और आंचलिक महायोजना के अनुसार के अधीन विनियमित होंगे।
(19)	विद्यमान स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(20)	विद्युत लाइनों का इन्सुलेशन।	भूमिगत केबल डालने का संवर्धन किया जाएगा। सभी विद्यमान विद्युत लाइनों जो पारिस्थितिक संवेदी जोन से होकर गुजरती हैं, को आंचलिक महायोजना के अधीन विहित समय-सूची में पर्याप्त रूप से इन्सुलेट किया जाएगा।
(21)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
(22)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	<p>लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।</p> <p>वन्यजीव के मुक्त संचलन को अनुज्ञात करने के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापना अपनी परिसंपत्तियों में काटेदार से बाड़ नहीं लगाएंगे और कोई भी बाड़ एक मीटर से ऊंची नहीं होगी। कोई विद्यमान बाड़, जो इस उपदर्श का अनुपालन नहीं करती है, को आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमा के अनुसार उपांतरित किया जाएगा।</p>

संवर्धित क्रियाकलाप		
(23)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(24)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(25)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(26)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(27)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
(28)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
(29)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (i) प्रभागीय आयुक्त, रायपुर - अध्यक्ष ;
- (ii) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ – सदस्य ;
- (iii) जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कबीरधाम, कवर्धा - सदस्य ;
- (iv) भारत सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट गैर सरकारी संगठन का (पर्यावरण, जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है, के क्षेत्र में कार्य करने वाला) - सदस्य ;
- (v) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (vi) कल्कटर, जिला कबीरधाम (कवर्धा) - सदस्य ;
- (vii) अधीक्षण इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, - सदस्य ;
- (viii) अधीक्षण इंजीनियर, लोक स्वास्थ्य विभाग इंजीनियर, - सदस्य ;
- (ix) नगर और गांव योजना का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (x) प्रभागीय वन अधिकारी, कबीरधाम, कवर्धा - सदस्य ;
- (xi) मुख्य वनपाल (डब्ल्यूएल) और क्षेत्र निदेशक उदन्ती – सीतानदी व्याघ्र आरक्षिती, रायपुर - सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन

- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.

का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध III** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/153/2015-ईएसजेड/आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य के सीमा वर्णन के साथ जी. पी.एस निर्देशांक

भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य के अक्षांश – देशांतर वर्णन के साथ जी. पी.एस निर्देशांक

क्र.सं.	अभयारण्य /राष्ट्रीय उद्यान नाम	विवरण	प्रकार	अक्षांश (डी.एम.एस)	देशांतर (डी.एम.एस)
1	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य एस	अभयारण्य बिंदु	एस1	22°13'34.23	81°3'16.7868
2	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस2	22°12'19.98	81°3'39.0852
3	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस3	22°10'40.6128	81°4'22.0332
4	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस4	22°7'10.8228	81°6'20.6676
5	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस5	22°4'55.6068	81°8'56.9256

6	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस6	22°2'24.8532	81°8'51.3456
7	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस7	22°0'0	81°6'32.8788
8	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस8	21°59'45.4776	81°2'49.9452
9	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस9	22°1'46.5168	81°2'28.4028
10	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस10	22°3'37.9584	81°1'42.9744
11	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस11	22°1'34.3884	80°58'39.8676
12	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस12	22°2'28.8384	80°56'45.1428
13	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस13	22°3'48.3156	80°53'51.1008
14	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस14	22°6'29.9844	80°54'33.8112
15	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस15	22°7'1.4808	80°56'43.728
16	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस16	22°3'28.674	80°59'47.85
17	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस17	22°6'34.4952	80°58'57.5256
18	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस18	22°7'56.1108	81°1'23.484
19	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस19	22°11'3.2964	81°1'4.9656
20	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस20	22°13'36.0408	81°1'19.6716

भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य- पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ

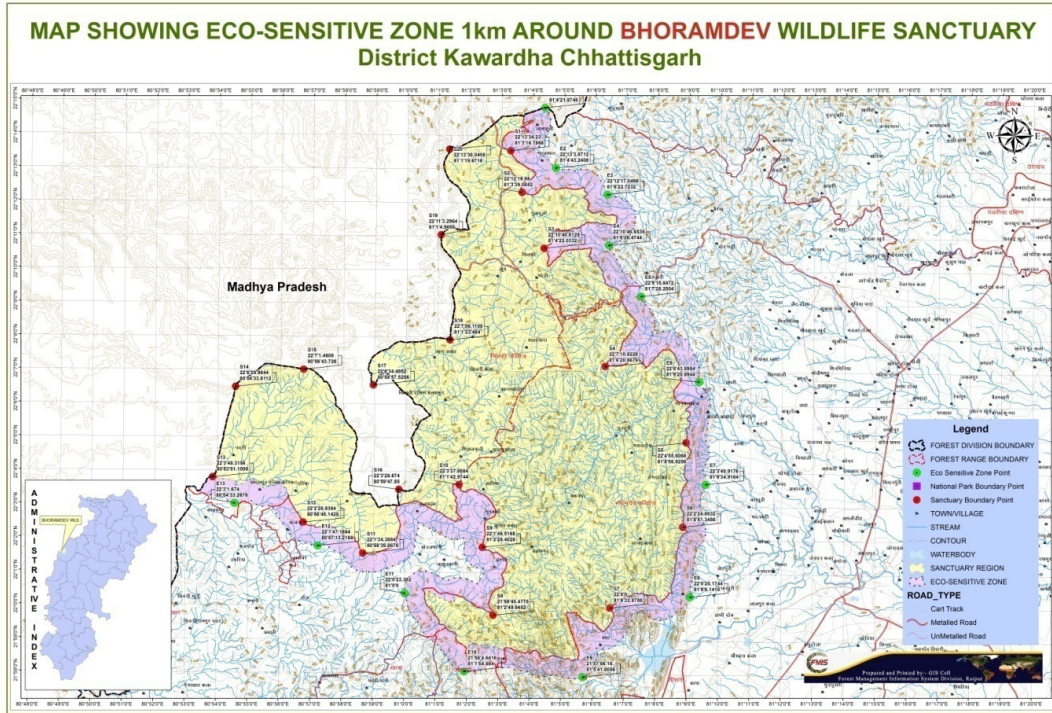
भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन जी.पी.एस निर्देशांक बिंदु

क्र.सं.	अभयारण्य नाम	विवरण	प्रकार	अक्षांश(डी.एम.एस)	देशांतर (डी.एम.एस)
1	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई 1	22°14'51.108	81°4'21.8748
2	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई 2	22°13'3.8712	81°4'43.2408
3	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई 3	22°12'17.0496	81°6'22.7232

4	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई 4	22°10'46.6536	81°6'26.4744
5	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई 5	22°0'20.1744	81°9'6.1416
6	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई 6	21°57'56.16	81°5'41.8056
7	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई 7	21°58'4.6416	81°1'54.894
8	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई 8	22°0'23.382	81°0'0
9	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई 9	22°1'47.1864	80°57'13.2156
10	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिक संवेदी बिंदु	ई 10	22°3'1.674	80°54'33.2676

उपाबंध II

अक्षांश और रेखांश के साथ भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य जोन का मानचित्र



उपाबंध-III**पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक् अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th April, 2016

S.O. 1362(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Boramdev Wildlife Sanctuary is situated in the Kawardha District in the State of Chhattisgarh and is spread over an area of 351.240 square kilometres.

AND WHEREAS, the sanctuary is an important protected area known for its rich habitat consisting of a variety of flora and fauna including Tiger, Leopard, Spotted Deer, Wild Pig, Langur, Peacock, Bear, Fox, Mongoose, Sambhar, Wild Dog, Blue Bull, Bison, Monkey, Hare, Hyeana, Python, Wild Cat, etc.

AND WHEREAS, the Boramdev Wildlife Sanctuary provides an extension to the Kanha Tiger Reserve as well as serves as a corridor for migration or movement of wild animals between the Boramdev Wildlife Sanctuary and the Achanakmar Tiger Reserve and also connects the Boramdev Wildlife Sanctuary and the Kanha Tiger Reserve and is located between the Kanha and Achanakmar Tiger Reserves.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Boramdev Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto one kilometer around the boundary of Boramdev Wildlife Sanctuary in district Kawardha, in the State of Chhattisgarh as the Boramdev Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone:- (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 109.882 square kilometres (including 87.53 square kilometres reserve or protected forest and 22.35 square kilometres revenue area) with an extent varying from 0 to one kilometer from the boundary of Boramdev Wildlife Sanctuary and the boundary description of such zone is appended as Annexure-I.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread across 15 villages, namely, Rajadhar, Ranidhara, Saraudadadar, Palak, Chaura, Sarkikachhar, Mandlatola, Bandha, Jharpat, Murwahi, Lariya, Jhalmala, Badalpani, Lahbar, and Samnapurtola.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment,
- (ii) Forest,
- (iii) Urban Development,
- (iv) Tourism,
- (v) Municipal,
- (vi) Revenue,
- (vii) Agriculture

- (ix) Chhattisgarh Environment Conservation Board,
- (x) Irrigation
- (xi) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restrictions on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said master plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The said master plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government:-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use:-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10,21,26,27,28 in column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

- (i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;
- (ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) rainwater harvesting; and
- (v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the, correction of error above shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs:-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism:-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Boramdev Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected areas till the extent of Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage:-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc., shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites:-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Chhattisgarh Environment Conservation Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution:-** The Environment Department of the State Government or Chhattisgarh Environment Conservation Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents:-** The discharge of treated effluents in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes:-** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste:-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic:-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.

(12) **Industrial units.-**

(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	<p>(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use.</p> <p>(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim orders of the Hon'ble Supreme Court, dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court, dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 435 of 2012.</p>

2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by State Level Committee shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 gradient and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallahs/ streams/ canals/ tributaries.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Undertaking activities related to tourism like over flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within 1kilometre of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities.
11.	Construction activities.	<p>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the protected area:</p> <p>Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3.</p> <p>(b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be allowed and other commercial construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.</p> <p>(d) Construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.</p>
12.	Trenching ground.	Establishing of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
13.	Discharge of effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
14.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
15.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government;

		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) In case of reserve forests and protected forests, the working plan prescriptions shall be followed.
18.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
19.	Existing establishments.	Regulated under applicable laws.
20.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
21.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
Permitted Activities		
23.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
24.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
25.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
26.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
27.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
28.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
29.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:

- | | | | |
|-----|---|---|----------|
| (a) | Divisional Commissioner, Raipur. | - | Chairman |
| (b) | An expert in the area of ecology and environment
to be nominated by the Government of Chhattisgarh
for a period of one year. | - | Member |
| (c) | Chief Executive Officer of District Panchayat, Kabirdham,
Kawardha. | - | Member |
| (d) | One representative of non-Governmental Organisation
(working in the field of environment including heritage
conservation) to be nominated by the Government of
India for a period of one year. | - | Member |

- | | | | |
|-----|--|---|-------------------|
| (e) | Representative of Chhattisgarh Environment Conservation Board . | - | Member |
| (f) | Collector, District Kabirdham (Kawardha). | - | Member |
| (g) | Superintendent Engineer, Public Works Department . | - | Member |
| (h) | Superintendent Engineer, Public Health Engineering. | - | Member |
| (i) | Representative of Town and Country Planning. | - | Member |
| (j) | Divisional Forest Officer, Kabirdham, Kawardha. | - | Member |
| (k) | Chief Conservator of Forest (WL) and field Director Udanti-Sitanadi Tiger Reserve, Raipur. | - | Member-Secretary. |

6. Terms of Reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure III**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/153/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I**Boundary details with GPS Co-ordinates of Bhoramdev Wildlife Sanctuary****Bhoramdev Wild Life Sanctuary with GPS Coordinates with Lat.Long detail**

SI.No.	Sanctuary/ NP Name	Description	TYPE	Latitude (DMS)	Longitude (DMS)
1	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S1	22°13'34.23	81°3'16.7868
2	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S2	22°12'19.98	81°3'39.0852
3	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S3	22°10'40.6128	81°4'22.0332
4	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S4	22°7'10.8228	81°6'20.6676
5	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S5	22°4'55.6068	81°8'56.9256
6	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S6	22°2'24.8532	81°8'51.3456
7	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S7	22°0'0	81°6'32.8788
8	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S8	21°59'45.4776	81°2'49.9452
9	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S9	22°1'46.5168	81°2'28.4028
10	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S10	22°3'37.9584	81°1'42.9744
11	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S11	22°1'34.3884	80°58'39.8676
12	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S12	22°2'28.8384	80°56'45.1428
13	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S13	22°3'48.3156	80°53'51.1008
14	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S14	22°6'29.9844	80°54'33.8112
15	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S15	22°7'1.4808	80°56'43.728
16	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S16	22°3'28.674	80°59'47.85
17	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S17	22°6'34.4952	80°58'57.5256
18	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S18	22°7'56.1108	81°1'23.484
19	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S19	22°11'3.2964	81°1'4.9656
20	Bhoramdev WLS	Sanctuary Point	S20	22°13'36.0408	81°1'19.6716

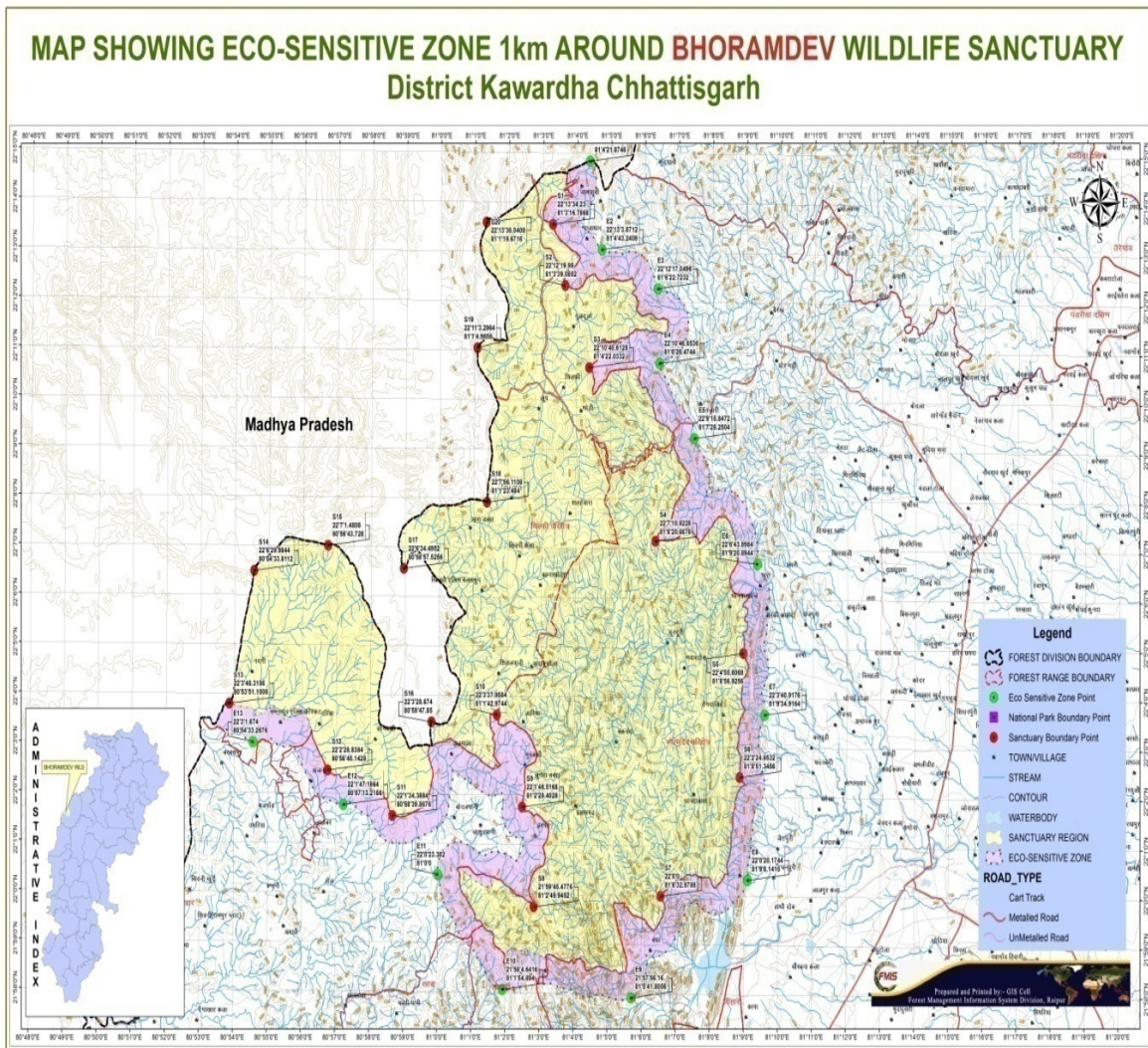
Bhoramdev Wild Life Sanctuary – Eco Sensitive Zone GPS Co-ordinates of points along the boundary of Eco-Sensitive Zone of Bhoramdev Wildlife Sanctuary

SI.No.	Sanctuary Name	Discription	TYPE	Latitude (DMS)	Longitude (DMS)
1	Bhoramdev WLS	Eco-Sensitive Point	E1	22°14'51.108	81°4'21.8748
2	Bhoramdev WLS	Eco-Sensitive Point	E2	22°13'3.8712	81°4'43.2408
3	Bhoramdev WLS	Eco-Sensitive Point	E3	22°12'17.0496	81°6'22.7232
4	Bhoramdev WLS	Eco-Sensitive Point	E4	22°10'46.6536	81°6'26.4744
5	Bhoramdev WLS	Eco-Sensitive Point	E5	22°0'20.1744	81°9'6.1416

6	Bhoramdev WLS	Eco-Sensitive Point	E6	21°57'56.16	81°5'41.8056
7	Bhoramdev WLS	Eco-Sensitive Point	E7	21°58'4.6416	81°1'54.894
8	Bhoramdev WLS	Eco-Sensitive Point	E8	22°0'23.382	81°0'0
9	Bhoramdev WLS	Eco-Sensitive Point	E9	22°1'47.1864	80°57'13.2156
10	Bhoramdev WLS	Eco-Sensitive Point	E10	22°3'1.674	80°54'33.2676

ANNEXURE-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BHORAMDEV WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES



ANNEXURE-III**Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise): Details may be attached as annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.